युद्ध हुआ तो चार दिन भी नहीं लड़ सकता पाकिस्तान

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के पास चार दिन का गोला बारुद भी नहीं है

नयी दिल्ली, 03 मई। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को पैसा कमाने के लिए यूक्रेन और इजरायल को बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बेचना महंगा पड़ रहा है और अब उसके खुद के पास चार दिन की लड़ाई लड़ने के लिए जरूरी गोला बारूद भी नहीं है।

विभिन्न रिपोर्टों तथा आंतरिक सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने यूक्रेन और इजरायल के साथ गोला बारूद बेचने के लिए जो सौदे किये, वे अब उसके गले की फांस बन गये हैं। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के गोला बारूद भंडार की स्थिति को देखकर यह कहना अतिशोयक्ति नहीं होगी कि लड़ाई की स्थिति में बिना गोला बारूद के चार दिन बाद उसके हथियार खिलौने बनकर रह जायेंगे।

रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान का गोला बारूद भंडार इतना कम हो गया है कि उसकी सेना किसी बड़े विरोधी के खिलाफ़ चार दिनों से ज़्यादा समय तक युद्ध का संचालन नहीं कर सकती। दरअसल 2022 में

- **रिपोर्टों के अनुसार, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपना गोला बारुद इज़रायल व यूक्रेन को बेचा था, और अब खुद उसके पास गोला बारुद नहीं बचा है।**

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को यूक्रेन-रूस लड़ाई में एक अवसर दिखाई दिया और पाकिस्तान के आयुध कारखाने यूक्रेन के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गए, जो गुप्त मार्गों से लाखों राउंड तोपखाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों के गोला-बारूद की आपूर्ति करते थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,000 122 मिमी बीएम -21 रॉकेट, 60,000 155 मिमी हॉवित्जर गोले और 130,000 122 मिमी रॉकेट भेजे, जिससे 36 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमाई हुई। इसमें से 80 प्रतिशत लाभ कथित तौर पर रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के जीएचक्यू में भेज दिया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, इन हथियारों का निर्यात आसमान छूकर 41 करोड़ 50 लाख डॉलर हो गया। इससे पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद का भंडार कम होना शुरू हो गया।

विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2025 तक पाकिस्तान का गोला-बारूद भंडार केवल 96 घंटे, यानी चार दिन के उच्च-तीव्रता वाले संघर्ष को झेल सकता है।

साथ ही रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान उच्च मुद्रास्फीति, बढ़ते कर्ज और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। इस वित्तीय उथल-पुथल ने सेना की संचालन क्षमताओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। ईंधन की कमी के कारण पाकिस्तान की सेना को राशन में कटौती करने, सैन्य अभ्यास स्थगित करने और निर्धारित युद्ध अभ्यास रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन सीमाओं को स्वीकार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत के साथ लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए गोला-बारूद और आर्थिक ताकत की कमी है। गोला-बारूद के भंडार में कमी और आर्थिक बाधाओं के कारण पाकिस्तान की सैन्य तैयारी में काफी कमी आई है। खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान ने संभावित संघर्ष की आशंका में भारत-पाकिस्तान सीमा के पास गोला-बारूद के डिपो बनाए हैं। हालांकि, मौजूदा कमी को देखते हुए इन उपायों से कितना फायदा होगा, यह बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की अपनी सैन्य तैयारियों पर इन हथियारों के हस्तांतरण के प्रभाव ने चिंता बढ़ा दी है। गोला-बारूद की कमी के कारण पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व भी गंभीर रूप से चिंतित है और दो मई को कोर कमांडरों के सम्मेलन में कई अन्य बातों के अलावा इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई।

राजस्थान बॉर्डर पर पाक रेंजर गिरफ्तार

गंगानगर, 03 मई। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ ने एक पाक रेंजर को पकड़ा है। यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को रेंजर्स की तरफ से पकड़े जाने के करीब 15 दिन बाद हुई

- **यह पाक रेंजर श्रीगंगानगर सीमा से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया।**

है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। मामले में अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी रेंजर को बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में ले लिया है। वहीं, बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ को रेंजर्स ने 23 अप्रैल को पंजाब में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर से पकड़ा था और भारतीय बल की तरफ से दर्ज कराए गए कड़े विरोध के बावजूद उन्होंने उसे सौंपने से इनकार कर दिया।

जानकारी के मुताबिक बीएसएफ इस पाकिस्तानी रेंजर से पूछताछ कर रही है कि वह किस मकसद से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था।

गोवा के शिरगांव में भगदड़ से 7 की मौत, 50 घायल

हादसा श्री लैराई जात्रा के दौरान हुआ, जिसमें 30 से 40 हजार लोग शामिल थे

गोवा, 03 मई। गोवा के शिरगांव में श्री लैराई जात्रा (यात्रा) के दौरान शुक्रवार रात मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। शनिवार सुबह मिली जानकारी के अनुसार, हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिनमें 20 गंभीर हैं। राहत-बचाव कार्य जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

शुक्रवार शाम को बड़ी संख्या में श्रद्धालु जात्रा में शामिल होने मंदिर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक दुकान के सामने बिजली के तार से करंट लगने के बाद कुछ लोग गिर गए। जिससे अफरा-तफरी हुई और भगदड़ मच गई। कहा जा रहा है कि क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से हादसा हुआ। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं।

श्री लैराई जात्रा नॉर्थ गोवा के बिचोलिम तालुका के शिरगांव गांव में आयोजित होने वाला हिंदू धार्मिक उत्सव है। जात्रा हर साल अप्रैल या मई में होती है।

इसमें गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस

- **यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जात्रा में शामिल होकर मंदिर जा रहे थे। यह यात्रा हर साल अप्रैल -मई में आयोजित होती है।**

वर्ष जात्रा 2 मई की शाम से 3 मई की सुबह तक आयोजित की गई थी, जिसके इसी दौरान हादसा हुआ।

गोवा पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित कई राज्यों के 30 से 40 हजार लोग यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। शुक्रवार शाम भीड़ मंदिर की ओर जा रही थी, तभी एक ढलान पर कुछ लोग गिर पड़े। इसके बाद पीछे से आ रहे लोग भी एक-दूसरे पर गिरते चले गए। 40 से 50 लोग इस दौरान नीचे गिर गए। इसके बाद अफरा-तफरी होने से भगदड़ मच गई।

यात्रा के लिए एक हजार पुलिसकर्मियों की ही तैनाती हुई थी। वहीं, भीड़ की एक्टिविटी को ड्रोन की मदद से ट्रैक किया जा रहा था।

भगदड़ मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए डीएम, एसपी और डीएसपी समेत कई अधिकारियों का तबदला कर दिया है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद सरकार ने कलेक्टर समेत कई अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा, गोवा के शिरगांव में भगदड़ के कारण हुई मौतों से दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घायलों का मुफ्त इलाज करने को कहा है। घटना पर गोवा कांग्रेस ने भी दुख जताया है।

पाकिस्तान पर और कड़े प्रतिबंध लगाए भारत ने

नई दिल्ली, 03 मई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने के संकल्प को दोहराये जाने के साथ साथ निरंतर कठोर निर्णयों से पाकिस्तान की नकेल कस रहे भारत ने शनिवार को भी पड़ोसी देश के खिलाफ़ कई दंडात्मक उपायों की घोषणा की, जिनमें पाकिस्तान के साथ डाक सेवाओं को निलंबित करना, उस देश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल के आयात पर प्रतिबंध लगाना और पाकिस्तानी ध्वज वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल हैं।

ये कदम जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ़ भारत की जवाबी कार्रवाई के तहत उठाये गये हैं। इस हमले में इस्लामी बंदूकधारियों ने 26 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी थी।

- **पाकिस्तान के साथ डाक सेवा पर प्रतिबंध।**
- **किसी भी किस्म के आयात पर रोक लगाई।**
- **पाकिस्तान के जहाजों का भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश निषेध।**

इस बीच, संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि भारत ने हवाई और सड़क मार्गों के माध्यम से पाकिस्तान से आने वाले सभी श्रेणियों के मेल और पार्सल के आदान-प्रदान को निलंबित करने का निर्णय लिया है। इससे पहले जहाजरानी महानिदेशालय ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम के तहत, एक निर्देश जारी कर पाकिस्तान के ध्वज वाले जहाजों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया और भारतीय ध्वज वाले जहाजों को पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने से रोक दिया। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भी शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना में, तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान से आने या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के आयात या पारगमन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने अटारी चौकी को पहले ही बंद कर दिया है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र व्यापार मार्ग है। पाकिस्तान ने भी भारत के कदमों के जवाब में इसी तरह की कई घोषणाएं की हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट आ गयी है।

नड्डा तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक नेताओं से मिले

मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारी पर चर्चा की गई

चेन्नई, 03 मई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने तमिलनाडु में अपने सहयोगी दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की तमिलनाडु इकाई की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति और तैयारी संबंधी कार्यों पर चर्चा और समीक्षा की गई।

बैठक में पार्टी नेताओं ने राज्य विधानसभा में भाजपा की संख्या बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा किया।

इसके लिए उन्होंने राज्य में एनडीए का नेतृत्व कर रही अन्नाद्रमुक और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने का वादा किया। इन सहयोगियों के गठबंधन में

- **भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने एक्स पर मीटिंग की जानकारी दी।**
- **नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि घर-घर जाकर मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दें।**

शामिल होने और सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) को सत्ता से बेदखल होने की संभावना है।

बाद में नड्डा ने एक्स पर लिखा, आज चेन्नई मे भाजपा तमिलनाडु की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की।

उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ हैं, जिसमें समृद्ध तमिल संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा, मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से घर-घर जाकर अभियान चला रहा है, तथा विकसित भारत के विजन में योगदान दे रहा है।

नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों से जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और चुनावों की तैयारी शुरू करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने का भी आग्रह किया। चुनाव एक साल से भी कम समय में होने वाले हैं।

नवनिर्वाचित भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता नैनार नागेन्द्रन, जो अन्नाद्रमुक के पूर्व कद्दावर नेता हैं और दक्षिणी जिलों में काफी प्रभाव रखते हैं, भाजपा के तमिलनाडु प्रभारी पी सुधाकर रेड्डी, संयोजक एच राजा, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन, जो विधायक भी हैं, पूर्व राज्य अध्यक्ष सुश्री तमिलिसाई सुंदरराजन, पोन राधाकृष्णन और अन्य वरिष्ठ नेता इस अवसर पर मौजूद थे।

गौरतलब है कि भाजपा ने अन्नाद्रमुक के एनडीए से बाहर निकलने के दो साल बाद, 2026 के महत्वपूर्ण चुनावों के लिए इस पार्टी के साथ संबंधों को फिर से मजबूत किया है।

इसकी घोषणा भाजपा के मास्टर चुनाव रणनीतिकार और केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने अन्नाद्रमुक महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी से नई दिल्ली में मुलाकात के बाद की।

एक ही मुद्दे पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के तथ्य की जानकारी नहीं दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए।

मामले की सुनवाई करते हुए, अदालत ने याचिका वापस लेने के आधार पर उसे खारिज करते हुए शिक्षा सचिव को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

राजनाथ सिंह नहीं जाएंगे रुस की विक्ट्री डे परेड में

नयी दिल्ली, 03 मई। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के मद्देनजर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बजाय अब रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ आगामी नौ मई को रूस में 'विक्ट्री डे परेड' समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

रूस ने इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया था लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बनी परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने रूस को बताया था कि प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और संभवत: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें भारत का

- **पाकिस्तान के साथ तनाव के माहौल को देखते हुए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रुस की विक्ट्री डे परेड में जाना कैंसल कर दिया है। रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ रुस जा सकते हैं।**

प्रतिनिधित्व करेंगे।

रक्षा सूत्रों ने शनिवार को बताया कि भारत पाकिस्तान के बीच के ताजा हालात तथा गतिविधियों को देखते हुए, अब रक्षा मंत्री की रूस यात्रा को टाल दिया गया है और उनकी जगह रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ रूस के विक्ट्री डे परेड के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे।

उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान को हर स्तर पर घेरने में जुटा है और इसके लिए निरंतर कदम उठाये जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वह इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों तथा हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।

जातिगत जनगणना के निर्णय के लिए मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया

परंतु मायावती ने यह भी कहा कि जनता के दबाव में मोदी सरकार को झुकना पड़ा

लखनऊ, 03 मई। केन्द्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने की बात कही गई है। इसे लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने बयान दिया है। एक्स पर मायावती ने लिखा, "साल 1931 व आजादी के बाद पहली बार देश में जातीय जनगणना कराने के केन्द्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस यह भूल गयी कि दलित व ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखना उसके इतिहास का काला अध्याय है व इस कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है। किन्तु सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का खासकर दलित व ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम विश्वास से परे, इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति है। वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अन्ततः इसको खत्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन

- **मायावती ने कहा, भाजपा व कांग्रेस दोनों में, खुद को ओबीसी शोषितों का हितैषी बताने की होड़ लगी है पर दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वोटों की राजनीति करते हैं।**

भुला सकता है?

मायावती ने लिखा, वैसे आरक्षण व संविधान के जनकल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं, बल्कि दोनों एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। किन्तु अब वोटों के स्वार्थ व सत्ता के मोह के कारण भाजपा को भी जातीय जनगणना की जन अकांक्षा के आगे झुकना पड़ा है, जिसका स्वागत है। साथ ही, संविधान निर्माता बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को भारतरत्न से सम्मानित करने से लेकर धारा 340 के तहत, ओबीसी को आरक्षण देने जैसे अनेक मामलों में कांग्रेस व भाजपा का रवैया जातिवादी व द्वेषपूर्ण रहा है, किन्तु इनके वोट की राजनीति के खेल निराले हैं। लोग सावधान रहें।

मायावती ने अगले पोस्ट में कहा, काफी लम्बे समय तक ना-ना करने के बाद अब केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी कराने के निर्णय का भाजपा व कांग्रेस आदि द्वारा श्रेय लेकर खुद को ओबीसी हितैषी सिद्ध करने की होड़, जबकि इनके बहुजन-विरोधी चरित्र के कारण ये समाज अभी भी पिछड़े, शोषित व वंचित। वैसे भी कांग्रेस एवं भाजपा आदि की अगर नीयत व नीति बहुजन समाज के प्रति पाक-साफ होती तो ओबीसी समाज देश के विकास में उचित भागीदार बन गया होता, जिससे इनके मसीहा परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का 'आत्म-सम्मान व स्वाभिमान' का मिशन सफल होता हुआ ज़रूर दिखता।

साबरकांठा : जीप, बस व बाइक की भिड़ंत में 6 की मौत, 8 घायल

हिम्मतनगर (गुजरात), 03 मई। गुजरात के साबरकांठा जिले में शनिवार को एक जीप, राज्य परिवहन की बस और एक दोपहिया वाहन की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।यह हादसा हिंगटिया गांव के पास एक राजमार्ग पर उस समय हुआ, जब जीप और बस में आमने-सामने की टक्कर हो गई और मोटरसाइकिल उसी समय दुर्घटनाग्रस्त जीप से टकरा गई।

महिला की हत्या...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिवादी बृजेश मीना ने खो-नागोरियान पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके माता-पिता गोनेर रोड स्थित पावर हाउस में करीब चार महीने से रह रहे हैं। वह 27 अगस्त 2023 को अपनी मां से मिलकर जगतपुरा गया हुआ था। दोपहर करीब 2 बजे रमेश मीणा ने फोन कर बताया कि उसकी मां को गौतम जाटव नाम के व्यक्ति ने चाकू से कई जगह वार कर घायल कर दिया है।

उसकी मां को एसएमएस अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अस्पताल में पांच दिन भर्ती रहने के बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी की और अपराध में काम में लिए गए चाकू सहित अन्य सामान की बरामदगी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।

कोर्ट में गवाहों ने बयानों में अभियुक्त की पहचान की और कहा कि भागन्ती देवी को चाकू मारने वाला गौतम ही था। वह जब महिला पर चाकू के कई वार कर भाग रहा था तो जनता ने उसे पकड़ लिया था और गेट से बांध दिया था। वहीं, एफएसएल रिपोर्ट में भी साबित हो गया कि अभियुक्त ने ही भागन्ती देवी की हत्या की थी।

बांग्लादेशियों को अवैध रुप से भारत लाने वाला शातिर गिरफ्तार

नई दिल्ली, 03 मई। देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों को अवैध रूप से भारत में एंट्री करवाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 40 से अधिक अवैध बांग्लादेशियों को भी पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। मामले की जांच की जा रही है। दरअसल, साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने यह कार्यवाही की है। यह मास्टरमाइंड करीब 10 साल से ज्यादा समय से बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री कराने के काम को अंजाम दे रहा था। यह पैसा लेकर बांग्लादेश से लोगों को भारत में लाकर बसाता था।

पायलट पति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पायलट पति के पास आय के पर्याप्त स्त्रोत हैं, लेकिन प्रार्थिया के पास आय के साधन उसके पति की तुलना में बहुत कम हैं। ऐसे में पत्नी अपने ससुराल में जिस स्तर का जीवन गुजारती, वही जीवन स्तर उसे पति से अलग रहने पर भी रखना चाहिए। इसलिए दोनों के जीवन स्तर को देखते हुए प्रार्थिया व उसकी बेटी को भरण-पोषण की राशि दिलवाना उचित होगा।

मामले से जुड़े अधिवक्ता डीएस शेखावत ने बताया कि प्रार्थिया का विवाह 2 मई 2014 को हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था। इस दौरान उसकी बेटी का जन्म हुआ। बेटी उसके पास ही रह रही है। शादी के बाद से ही उसे ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करने लग गए। वे उसे शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगे। इसके चलते, उसने 15 नवंबर 2018 को पति व उसके घरवालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, घरेलू हिंसा का मामला भी विचाराधीन है। उसका पति इंडिगो एयरलाइंस में कैप्टन के पद पर है और उसे प्रति माह 6.50 लाख रुपए वेतन मिलता है। वहीं, अन्य संसाधनों से भी उसकी काफी आय होती है। इसलिए उसे अपने व बेटी के लिए 3 लाख रुपए भरण पोषण राशि दिलवाई जाए।

इसके जवाब में पति ने कहा कि उसने प्रार्थिया को प्रताड़ित नहीं किया है और पार्थिया पायलट है व उसकी आय हर महीने1.80लाख रुपए है। वह खुद का और बेटी का भरण-पोषण करने में सक्षम है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर पति को पत्नी व बेटी को हर महीने 1.40 लाख रुपए भरण-पोषण भत्ता देने का निर्देश दिया।

प्रदेश के छोटे खान बजरी मालिकों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आई.ए.एस. अफसर राजीव स्वरूप को एस.ई.आई.ए.ए. का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति से पूर्व कुछ समय तक तो यह पद रिक्त पड़ा हुआ था।

जैसा कि विदित है, राजीव स्वरूप, गहलोत सरकार के दौरान हुए सचिन पायलट गुट व मंत्रिमंडल के कुछ विधायकों के फोन टैपिंग प्रकरण के दौरान गृह सचिव के पद पर कार्यरत थे, जिसके बाद उन्हें मुख्य सचिव के पद पर भी नियुक्त किया गया था, परंतु केन्द्र सरकार से एक्सटैंशन नहीं मिलने के कारण तीन महीने के भीतर उन्होंने मुख्य सचिव के पद से रिटायरमैंट लिया, जिसके कुछ समय बाद ही उन्हें एस.ई.आई.एस. का अध्यक्ष बना दिया गया।

खनन विभाग के सूत्रों के अनुसार राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में एस.ई.आई.ए.ए. ने बजरी खनन करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु दायर 16 हजार से भी अधिक आवेदनों में से केवल 4,500-5,000 आवेदनों को ही स्वीकृति दी। करीब दो-ढाई हजार आवेदनों को अस्वीकार किया और शेष आवेदनों पर कोई फैसला नहीं सुनाया, जिस वजह से बजरी खनन के उद्योग से जुड़े कई उद्योगपति आज भी प्रभावित हैं।

उल्लेखनीय है कि गहलोत सरकार के जाते ही वर्तमान सरकार ने एस.ई.आई.ए.ए. के पुर्नगठन की प्रक्रिया शुरु कर दी। परंतु सुप्रीम कोर्ट में एन.जी.टी. के आदेश के खिलाफ अपील भी दायर की गई और राजस्थान से बजरी खनन मालिकों की तरफ से आवेदन भी दायर किये गये कि एस.ई.आई.ए.ए. उनके आवेदनों की जाँच-पड़ताल करे बिना, उन्हें खारिज नहीं कर सकता।

सभी तथ्यों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 12 नवबंर को छोटे खान मालिकों को राहत दी थी और कहा था कि राजस्थान सरकार मार्च 2025 तक एस.ई.आई.ए.ए. के सभी सदस्यों को नियुक्त कर बचे हुए बजरी खनन आवेदनों पर फैसला सुनाए। परंतु सरकार ने अभी तक भी एस.ई.आई.ए.ए. के सभी सदस्यों को नियुक्त नहीं किया है। इस वजह से बजरी खनन करने के लिए दायर सभी आवेदनों पर फैसला नहीं लिया जा सकता है।

इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक मई को सुनवाई के बाद आदेश जारी किए और कहा कि एस.ई.आई.ए. आवेदनों पर कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, "फैसला लेने के लिए दो महीनों का अतिरिक्त समय ले सकता है और एस.ई.आई.ए.ए. को अगली सुनवाई पर अपना जवाब भी प्रस्तुत करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जिन आवेदनों को एस.ई.आई.ए.ए. जाँच कर पहले ही बजरी खनन की अनुमति दे चुका है, उन पर किसी भी तरह की रोक न लगाई जाए, जिससे करीब 5000 छोटे खान व्यवसायियों को राहत मिली है।

तेजस्वी यादव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है उससे वंचित वर्गों और हाशिए पर रहे लोगों की मांगों की पुष्टि होती है।

यादव ने लिखा बिहार कास्ट सर्वे से पता लगा कि राज्य में 63 प्रतिशत ओबीसी एवं ईबीसी है। उम्मीद है ऐसे ही नतीजे राष्ट्रीय स्तर पर निकलेंगे।

हालिया वर्षों में जातिगत जनगणना की मांग ने काफी जोर पकड़ा था साथ ही भारत की जनसंख्या में सामाजिक आर्थिक लाभों के वितरण में पारदर्शिता की मांग भी उठ रही थी।

जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे लोगों को डर है कि क्या सरकार इसके नतीजों पर कार्यवाही करने की मंशा रखती है। यादव ने कहा जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की लम्बी यात्रा में मात्र पहला कदम है। उन्होंने कहा आरक्षण पर लगी सीमा पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

'2016 की सर्जिकल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सकता है।

उनका तर्क है कि इन उपायों के जरिए भारत वैश्विक आलोचना और सीधे युद्ध को न्यौता दिए बिना ही, पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाने पर मजबूत कर सकता है।

रिटायर्ड कर्नल व रक्षा विश्लेषक वी.एस. नायर के अनुसार, "हम एक दृष्टिकोण परिवर्तन देख रहे हैं। यह एक नई नीति बन रही है, जिसमें कठोर सैन्य शक्ति के साथ-साथ राजनीतिक संचालन के तकनीकी, कूटनीतिक और आर्थिक साधन शामिल हैं। यह पारंपरिक युद्ध के जाल में फंसे बिना सबक सिखाने का तरीका है।"

इसी बीच, कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार, भारत ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से संपर्क कर उन्हें सीमा पार बढ़ रही भड़काने वाली गतिविधियों और पहलगाम हमले की गंभीरता के बारे में जानकारी देना शुरु कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को लेकर एक मजबूत वैश्विक समर्थन तैयार करना है।

ज़मीनी स्तर पर, नियंत्रण रेखा पर तैनात सैनिक "हाई अलर्ट" पर हैं। वहाँ पक्के बंकर, उन्नत निगरानी प्रणालियां और बेहतर गतिशीलता संसाधन तैनात किए गए हैं। ज़मीनी रिपोर्टों के अनुसार, सैनिकों का मनोबल ऊँचा है और वे किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं।

हालांकि, संभावित कार्रवाई की समय सीमा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि भारतीय सैन्य तंत्र किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस समय सरकार की चुप्पी ही भविष्य की कार्यवाही को लेकर उत्सुकता को बढ़ा रही है।

जैसा कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने संक्षेप में कहा, "हम तैयार हैं। अगला कदम खुद बोलेगा।"

एनआईए ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आरोप पत्र दायर किया था।

इस बीच, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2008 के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड राणा की अपील को खारिज कर दिया था। उसके बाद, राणा को भारतीय हिरासत में भेजने का रास्ता साफ हो गया था।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्यो